



SSC GK

PARMAR'S GK BATCH

TOPIC

**Parliamentary
Committee & Emergency**

Lecture :- 10

✓ **For Notes Join Telegram :**



Click on the icon.

OR
Scan



✓ **For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel**



Click on the icon.

OR
Scan



1/6 सदस्य - राज्यपाल द्वारा मनोनीत

(साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा, सहकारी संस्था)



1- स्थली इंडियन राज्यपाल द्वारा.

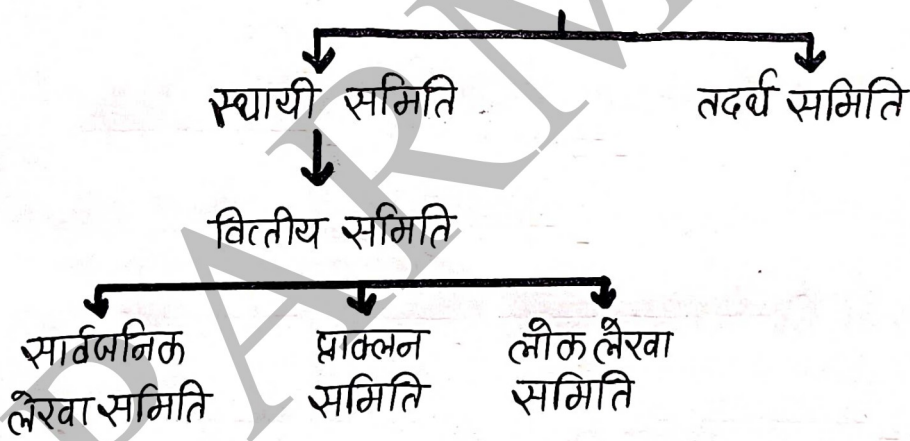
↳ 104th संविधान संशोधन द्वारा खत्म

↳ SC/ST का आरक्षण बढ़ाया गया।

- शैक्षणिकता : विधानसभा - 25 साल
विधानपरिषद - 30 साल
- शपथ : राज्यपाल
- व्यापकता : पीठासीन अधिकारी
- सत्रावसान / विघटन → राज्यपाल
- साधारण विल : लोकसभा विधान राज्यपाल

लोकसभा

संसदीय समिति



समानताये - इनका सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है।

→ कार्यकाल = 1 वर्ष

→ चुनाव - आनुपातिक प्रतिनिधित्व + एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा

→ सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष / स्पीकर द्वारा मनोनीत।

→ स्पीकर / अध्यक्ष के निर्देश में काम करना।



असमानतारें:

सार्वजनिक लेखा समिति:

स्थापित/गठन - भारत शासन अधिनियम 1919, 1921

सदस्य = 30
└──┬──
लोकसभा RS
15 7

काम = नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किये गये लेखा-परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करना।

प्राक्कलन समिति:

ऑन मर्चाई समिति की सिफारिश पर गठन

गठन - 1950

सदस्य = 30 सभी लोकसभा से
(25, 1956 से 30)

कार्य = बजट में शामिल अनुमान (estimates) की जांच करना।

लोक लेखा समिति:

गठन - 1964, कृष्णा मैनन समिति की सिफारिश पर

सदस्य = 22

└──┬──
15 LS 7 RS

15 सदस्य → 22 सदस्य
1974

अध्यक्ष = केवल लोकसभा से

कार्य - जनता की रिपोर्ट और खाते की जांच करना।

विभागा संबंधी स्थायी समिति:

24 समिति
└──┬──
16-LS 8-RS

सदस्य = 31
└──┬──
21 LS 10 RS

निम्नी सदस्यो के विधीयतो और संकल्पो पर समिति:

अध्यक्ष = लोकसभा का उपाध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष { व्यापार सलाहकार समिति
नियम समिति
सामान्य प्रयोगन समिति

राजभाषा पर संसदीय समिति = 1976 में गठित

30 सदस्य

20 लोकसभा 10 राज्यसभा

संवैधानिक संशोधन

संशोधन - भाग 20

↳ अनु० 368, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया।

→ संसद, संविधान के मूल ढाँचे के अलावा कुछ भी संशोधित कर सकती है। (केशवा भारती मामला 1973)

प्रक्रिया / procedure:

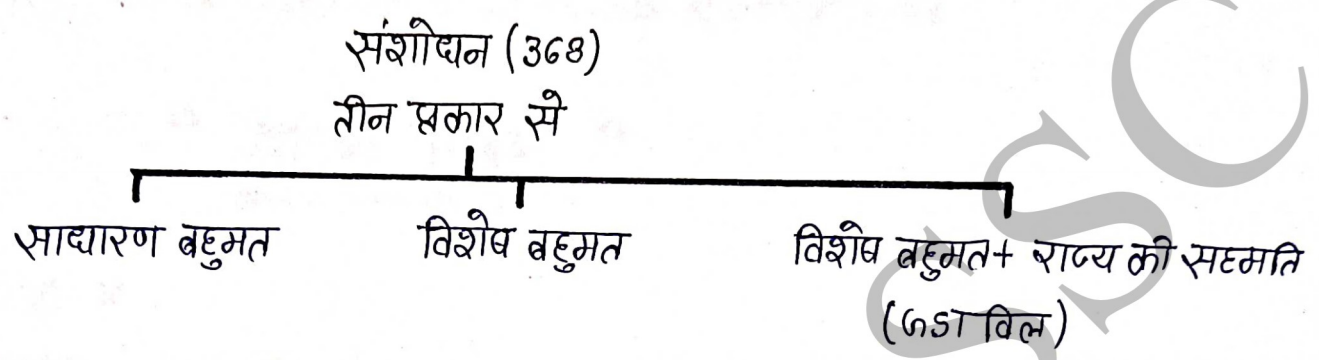
- संविधान संशोधन बिल को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है लेकिन राज्य विधानमण्डल में नहीं।
- इसमें या तो मंत्री या प्राइवेट सदस्य कोई भी ला सकता है।
- इसको लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- बिल विशेष बहुमत से पास होना चाहिए।
- कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती।
- राष्ट्रपति को सहमति देने ही होगी। कोई वीटो शक्ति उपयोग नहीं कर सकता। (24 वां संविधान संशोधन)





के. सी. व्हीयर - " भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। "

न ही USA जितना कठोर , न ही UK जितना लचीला ।



विशेष बहुमत :

- ⊙ मौलिक अधिकार
- ⊙ DPSP (नीति निर्देशक तत्व)

विशेष बहुमत + कम-से-कम आधे राज्यों की सहमति :

- ⊙ राष्ट्रपति का चुनाव एवं प्रक्रिया
- ⊙ सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची
- ⊙ संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
- ⊙ SC/HC से संबंधित
- ⊙ विद्यार्थी शक्तियों का वितरण
- ⊙ अनुच्छेद 368

- पहला संविधान संशोधन 1951 → 9 वीं अनुसूची
'कुछ राज्यों में कुछ सुधारों से संबंधित'
- राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने किस संशोधन को मंजूरी दी- 100वां संवि. संशोधन
- गाँवा को राज्य का दर्जा- 56वां संवि. संशोधन
UT का दर्जा- 12वां संवि. संशोधन

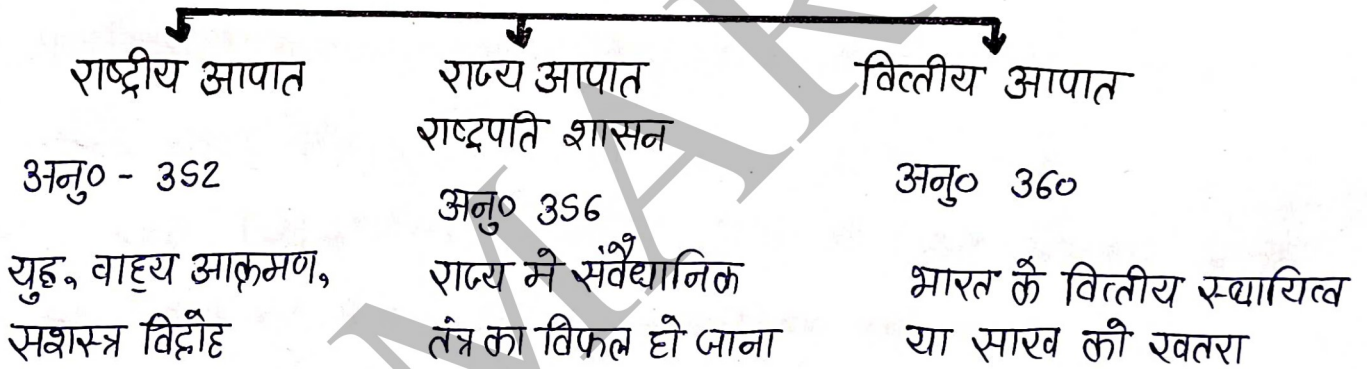
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन-2005
- किस संशोधन द्वारा संघ सूची में 'सेवाओं पर कर' नामक एक नया विषय जोड़ा गया- 88^{वां}
- मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष- 61 वां संवि. संशोधन 1989
- भारत का लघु संविधान- 42 वां संवि. संशोधन 1986

“ आपात उपबंध ”

भाग - 18

अनुच्छेद : 352 - 360 ' भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया '

आपात



↓

वीक्षण- राष्ट्रपति
(कौन्सिल की मंजूरी)
(44 वां संविधान संशोधन)

मंजूरी = 1 महीना का विशेष बहुमत से

$\begin{matrix} \swarrow & \searrow \\ LS & RS \end{matrix}$

मंजूरी मिलने पर 6 महीने तक लागू

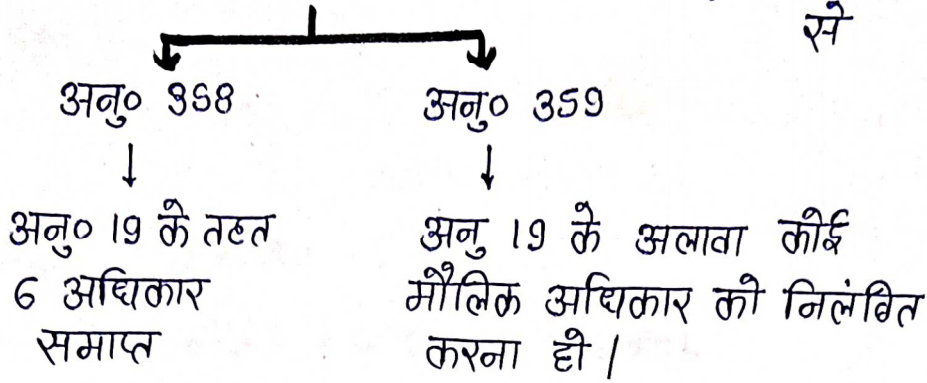
पुनः मंजूरी - 44 वां संविधान संशोधन

द्वारणा → राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम समय = अनिश्चित

→ लोकसभा द्वारा स्थापना बहुमत से टटायल जा सकता ।

प्रभाव: मौलिक अधिकारों पर:

(जर्मनी के संविधान)
से



- अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किये जा सकते हैं।
- सशस्त्र विद्रोह के समय अनु० 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता।

○ आंतरिक विद्रोह $\xrightarrow{\text{44 वां संविधान संशोधन}}$ सशस्त्र विद्रोह

- कार्यकारी (Executive) → केन्द्र किसी भी मामले पर राज्य को निर्देश (direction) दे सकता है।
- विधायिका (Legislative) → संसद किसी भी विषय और राज्य सूची पर कानून बना सकती है (6 महीने तक अधिकतम)

मिनर्वा मिल्स मामला → राष्ट्रीय आपातकाल लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

राष्ट्रीय आपात → 3 बार { 1962
1971
1975

अनुच्छेद 355: राज्यों में आंतरिक गडबडी रोकने और शांति स्थापित करना केन्द्र सरकार का दायित्व है।

अनुच्छेद 356: राष्ट्रपति शासन
संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर

- ◉ आचार {
 - 356 - संवैधानिक तंत्र का विफल होना
 - 365 - जब राज्य, केन्द्र द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन न करे।
- ◉ घोषणा- राष्ट्रपति
- ◉ मंजूरी- संसद (within 2 months)
 - साधारण बहुमत से
 - मंजूरी मिलने पर 6 महीने तक।
 - अधिकतम समय = 3 वर्ष
- ◉ टटाना- राष्ट्रपति द्वारा कभी भी।
 - संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं।
- ◉ प्रभाव- मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं।
 - मंत्रिपरिषद (Cmns) को बख्ति कर दिया जाता।
 - राज्यविधानसभा को निलंबित कर दिया जाता।
- SR वीम्बई मामला संबंधित
- ◉ पहली बार राष्ट्रपति शासन- पंजाब (1951)
 - ◉ अधिकतम बार- मणिपुर (10 बार)
 - UP (9 बार)